



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4385/2026

रणजीत

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अजय कुमार यादव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.के. निषाद को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 02/2026, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना टुण्डला, जिला फिरोजाबाद में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और किसी छिपे उद्देश्य के कारण उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास की व्याख्या जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित समस्त मामलों में आवेदक पहले से ही जमानत पर मुक्त है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण अथवा सहायता नहीं की है। आवेदक का उक्त प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक, जो दि० 02.01.2026 से कारागार में बन्द है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता को दृष्टिगत रखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर निर्भरता रखी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों की लम्बितता स्वयं में जमानत अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गैंग-चार्ट में प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला भी इंगित नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित प्रकरण पाता हूँ। अतः यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **रणजीत** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डरायेगा-धमकायेगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) कथन अभिलेखन की नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिमत की अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”